लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1364

02 मई, 2016 को उत्तर के लिए

नई इस्पात नीति

1364. डॉ. के. कामराज:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस्पात की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है जिससे इस्पात की आयात पर निर्भरता बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भविष्य की जरुरतों को पूरा करने के लिए सरकार का एक नई राष्ट्रीय इस्पात नीति बनाने का प्रस्ताव है, क्या देश में इस्पात क्षेत्र में आ रही चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए सरकार ने नई उप-समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नई नीति को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): जी, नहीं। इस्पात की घरेलू मांग और आपूर्ति के बीच अंतर आयातों से परिलक्षित होता है। समस्त फिनिश्ड स्टील के संबंध में घरेलू खपत (80.45 मिलियन टन)का केवल 15 प्रतिशत आयात (11.71 मिलियन टन) हुआ है जिसका आशय है कि एक बड़े भाग की खपत विक्रय हेतु घरेलू उत्पादन में की गई थी, (90.39 मिलियन टन)।

(ग) और (घ): जी, हां। इस्पात मंत्रालय ने एक संशोधित राष्ट्रीय इस्पात नीति तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ की है।

***